भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1175

01.08.2024 को उत्तर के लिए

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यावरणीय खतरे

1175. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जलवायु संबंधी कारकों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यावरणीय खतरों की घटनाओं में वृद्धि की है;

(ख) मणिपुर में आश्रय, आजीविका (आय), स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं की सुलभता और सामान्य गतिशीलता के मामले में विस्थापित आबादी पर अचानक आई बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) पूर्वोत्तर के साथ-साथ देश में जलवायु संबंधी इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) को दिसम्बर, 2023 में प्रस्तुत तीसरे राष्ट्रीय संसूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन और वर्षा एवं तापमान में दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ चरम मौसमी घटनाओं का अनुभव हुआ है। इन घटनाओं में चक्रवाती तूफान, सूखा, बाढ़, बिजली गिरना, आंधी-तूफान, बर्फबारी, शीत लहरें और गर्म लहरें शामिल हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 'मानकीकृत वर्षा सूचकांक' (एसपीआई) का उपयोग करके भारत में वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक शुष्क और गंभीर शुष्क स्थिति देखी गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित प्रमुख राज्यों की संख्या वर्ष 2017 में 08 राज्यों से बढ़कर वर्ष 2021 में 15 हो गई। भारी वर्षा और बाढ़ की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रायद्वीपीय, पूर्व, पूर्वोत्तर सहित भारत के कुछ भागों और मध्य भारत के कुछ भागों में इनकी आवृत्ति बढ़ रही है।

(ख) मणिपुर की जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के अनुसार, यह राज्य पूर्वी हिमालय की सीमा में स्थित होने, नाजुक भू-पर्यावरणीय स्थिति और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण जल-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। घाटी क्षेत्रों में तूफान के कुछ समय बाद ही बार-बार बाढ़ आती है, जिसके कई कारण अर्थात जलग्रहण क्षेत्रों में मानव द्वारा किए गए पारिस्थितिकीय परिवर्तन, पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्ष होना हैं। वर्षा ऋतु के

दौरान अचानक आने वाली बाढ़ से कृषि भूमि, पर्यावास तथा शहरी बस्तियां प्रभावित होती हैं। बाढ़ के कारण होने वाली क्षति में संवेदनशील क्षेत्रों में बांधों का टूटना, अतिप्रवाह, भूस्खलन, मृदा अपरदन और नदी के किनारों का धंसना शामिल है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर राज्य-विशिष्ट अध्ययनों से फसल की पैदावार में कमी होने, खराब फसल उत्पादन से आय में कमी होने, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी समस्याएं बढ़ने, वेक्टर जनित बीमारयों के बढ़ने और लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होने के संकेत मिलते है।

(ग) सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को क्रियान्वित कर रही है, जो सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशनों और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के माध्यम से जलवायु कार्यवाई के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इन मिशनों को संबंधित नोडल मंत्रालयों और विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है।

एनएपीसीसी के अनुरूप, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए अपनी-अपनी एसएपीसीसी तैयार की है। सभी एसएपीसीसी ने चरम मौसमी घटनाओं में परिवर्तन के कारण होने वाली आपदा से जोखिम को कम करने का आह्वान किया है, जिसमें जोखिम भेद्यता आकलन रिपोर्ट (एचआरवीए), राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) और राज्य आपदा प्रबंधन दल (एसडीआरएफ) बनाए जाना शामिल है।

आपदा जोखिम प्रबंधन और उसके न्यूनीकरण के लिए चरम मौसमी घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए ज्ञान और क्षमता विकसित करना एक व्यापक लक्ष्य है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

i. भारत के बाढ़-संभावित क्षेत्रों में स्थानिक बाढ़ की चेतावनी प्रदान करने के लिए वेरी हाई-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल टेरेन मॉडल का उपयोग करके स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल का विकास किया गया है। वेब-सक्षम अर्ध-स्वचालित स्थानिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के डेटा तैयार करने में सहयोग के साथ वास्तविक समय में परिचालन मोड में संचालित होती है, और इसके परिणाम भू-पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।
ii. बाढ़ और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का आकलन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संगठन (इसरो) - आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत त्वरित प्रतिक्रिया और आपातकालीन सेवाएं/निर्णय सहायता केंद्र (आररआरईएस/डीएससी) की स्थापना की गई है।
iii. आईएमडी गर्मी के मौसम में मौसमी पूर्वानुमान का नियमित आकलन करता है और अलग-अलग समय और स्थानिक पैमानों पर भारत में दैनिक तापमान का पूर्वानुमान उपलब्ध करवाता है। इनका उपयोग भीषण गर्मी की तत्काल पूर्व चेतावनी देने के रूप में किया जाता है।

*****